सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)
(Seventh Five Year Plan, 1985-90)

सातवीं योजना के मुख्य उद्देश्य वही थे जिनका उल्लेख पहले की योजनाओं में किया गया था। इस तरह इस योजना में भी संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर जोर था। लेकिन इस बात को समझते हुए कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक न्याय की दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं हुई, योजना आयोग ने सातवीं योजना में इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति होनी चाहिए और रोजगार विस्तार और गरीबी निवारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्पादक रोजगार से लोगों में आत्मविश्वास पैदा होता है और इससे उनकी विकास कार्यों में भागीदारी बढ़ जाती है। रोजगार के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोजक अब रोजगार में विस्तार के लिए महज आर्थिक संवृद्धि पर निर्भर नहीं रहना चाहते। **सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसलिए रोजगार को एक सीधा और अपने आप में महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना गया था। लेकिन योजना आयोग की राय में रोजगार को स्थायी रूप से बनाये रखने के लिए उसका उत्पादक होना जरूरी है। तात्पर्य यह है कि रोजगार में विस्तार के द्वारा उत्पादन और आय में निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए।**

छठी योजना शुरू होने के समय ऊर्जा और यातायात समस्याएं काफी गंभीर रूप धारण किए हुए थीं। इनकी वजह से सारी विकास प्रक्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। यह स्थिति इन क्षेत्रों में भारी निवेश के बावजूद पैदा हो गई थी। सातवीं योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि आधारभूत ढांचे (infrastructure) में जो भी निवेश किया हो उसका उचित नतीजा निकले। ऐसा होने पर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में आने वाली कुछ बाधाएं दूर हो सकती हैं।

Scanned with CamScanner

सातवीं पंचवर्षीय योजना का संवृद्धि लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हासिल करना था। संवृद्धि की यह दर-उससे थोड़ी ऊंची थी जो पिछले दशक में वास्तव में हासिल की जा सकी थी। योजना आयोग ने इस लक्ष्य को तय करते समय विभिन्न वैकल्पिक विकास संभावनाओं पर विचार किया था और वह आखिर में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि दीर्घकाल में मांग का जो भी स्वरूप बनेगा उसके अनुरूप लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि ही है।

उपरोक्त मुख्य उद्देश्यों के अलावा सातवीं योजना के दस्तावेज में कुछ अन्य उद्देश्यों का जिक्र भी था। इनमें तेज संवृद्धि वाले क्षेत्रों में तकनीकी सुधार, मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण और लोगों के भौतिक कल्याण तथा उस पर्यावरण (environment) में जिसमें वे रहते हैं, सुधार, शामिल है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)
(Eighth Five Year Plan, 1992-97)

आठवीं पंचवर्षीय योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई दिशाओं में काम करने की दृष्टि से तैयार की गई थी। अतः **रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न करना इस योजना का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था।** आठवीं योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे :

1. पर्याप्त रोजगार अवसरों का सृजन ताकि बीसवीं शताब्दी के अन्त तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
2. लोगों के सहयोग द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकना।
3. सभी को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा 15-35 के आयु वर्ग में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन।
4. सुरक्षित पेयजल का प्रावधान तथा सभी गांवों में और समूची आबादी के लिए रोग-प्रतिरोधी टीका लगाने समेत प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
5. कृषि के क्षेत्र में संवृद्धि और विविधीकरण ताकि खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ-साथ निर्यात के लिए भी अधिशेष (surplus) प्राप्त किया जा सके।
6. ऊर्जा, परिवहन, संचार, परिवहन को मजबूत बनाना।

इन उद्देश्यों के अनुसार काम करते हुए आठवीं योजना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया : (*i*) निवेश कार्यक्रमों के लिए वित्तीय साधन एकत्रित करने के लिए घरेलू संसाधनों (domestic resources) पर निर्भरता; (*ii*) विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तकनीकी क्षमता में वृद्धि; तथा (*iii*) आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर जोर ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में हो रही प्रगति के साथ कदम मिलाकर चल सके।

आठवीं योजना में मानव विकास पर खास ध्यान दिया गया। रोजगार सृजन, जनसंख्या नियन्त्रण, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल उपलब्ध कराना, पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, आधारभूत संरचना का विकास इत्यादि सभी प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों का उद्देश्य इसी मानव विकास को प्राप्त करना था। मानव-पूँजी (human capital) के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की मौलिक जिम्मेदारी सरकार की मानी गई। यह बात हैरानी की लगती है कि उद्देश्यों की उपरलिखित सूची में आर्थिक संवृद्धि को शामिल नहीं किया गया। परन्तु यदि हम योजना के लक्ष्यों की ओर ध्यान दें तो देखेंगे कि आठवीं योजना में आर्थिक संवृद्धि का लक्ष्य 5.6 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया था जो सम्पूर्ण योजना अवधि में प्राप्त संवृद्धि दर से अधिक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आठवीं योजना में भी आर्थिक संवृद्धि का महत्त्वपूर्ण स्थान बना रहा।

पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय कुशलता के साथ-साथ योजना के उद्देश्यों के प्रति ईमानदारी जरूरी थी। इसके लिए आयोजन की विकेन्द्रित प्रक्रिया की भी आवश्यकता थी ताकि योजना लागू करते समय लोगों की उसमें भागीदारी की गुंजाइश हो।

Scanned with CamScanner